

प्रेषक,

सौरभ जैन
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड।

ऊर्जा अनुमान-१

देहरादून: दिनांक ।। अगस्त, २००९

विषय:- वित्तीय वर्ष २००९-१० में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिए अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय विभाग के शासनादेश संख्या-५१५/xxvII(1)/२००९ के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष २००९-१० में उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को संलग्नक में वर्णित लेखाशीर्षकों में जनपदवार जिला सेक्टर में अनुसन्धित जाति के कल्याणार्थ रु० 13626-०० हजार (एक करोड़ छत्तीस लाख छव्वीस हजार मात्र) की धनराशि (शासनादेश संख्या ८३० /।/२००८-०३(१)/२१/०८ दिनांक २-६-२००९ के द्वारा पूर्व में स्वीकृत रु० 4543 हजार की धनराशि को समिलित करते हुए) निम्न शर्तों के लधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

१- जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जिला नियोजन एवं अनुक्षण समितियों द्वारा अनुमोदित योजनावार एवं ज्ञान परिव्यय के अनुसार ही धनराशि कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करेंगे।

२- व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैंडबुक, स्टोर पर्चेज मूल्य मितव्ययता टेंडर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।

३- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मद्दार व्यय विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को दिनांक ३१.३.२०१० तक उपलब्ध करा दिया जायेगा।

४- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से सत्तरदायी होंगे।

५- केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं पर केन्द्रांश एवं राज्यांश अवमुक्त किये जाने के बाद ही कोषागार से आवश्यक धनराशि का आहरण किया जायेगा।

६- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसे प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

७- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक ३१.३.२०१० तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

८- जिलाधिकारियों द्वारा कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने पर सम्बन्धित जिलाधिकारी

के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी। भारत सरकार से वित्त पोषित योजनाओं का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय प्रेषित कर दिया जायेगा।

9— जिलाधिकारियों द्वारा उक्त प्रस्तर-1 में वर्णित शासनादेश दिनांक 28.7.2009 में निहित शतों का अक्षरशः पालन किया जायेगा।

10— रु० 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति सम्बन्धित मण्डलायुक्त से सहमति प्राप्त कर जारी की जायेगी।

11— नये कार्यों पर व्यय करने से पूर्व इनके विस्तृत आगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति शासन एवं सक्षम स्तर से प्राप्त की जायेगी।

12— सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा उक्त धनसाशि का मासिक व्यय विवरण का रजिस्टर दी०एम०-८ के प्रपञ्च पर रखा जायेगा और पूर्व के माह को व्यय का विवरण उक्त अधिकारी के द्वारा अनुवर्ती माह की ०५ तारीख तक उक्त अनुदान के नियन्त्रक अधिकारी को बजट मैनेजर के अध्याय-१३ के प्रस्तर-११६ की व्यवस्थानुसार प्रेषित किया जायेगा और प्रस्तर-१२८ की व्यवस्थानुसार उक्त अनुदान के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा पूर्ववर्ती माह का रांगत व्यय विवरण अनुवर्ती माह की २५ तारीख तक वित्त विभाग को प्रेषित किया जायेगा और यदि नियमित रूप से शासन को उक्त विवरण प्रेषित नहीं किया जाता है तो उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक (मा० मुख्यमंत्री जी/मुख्य सचिव) अर्थात् सक्षम स्तर को कार्यवाही करने हेतु अवगत कराया जायेगा।

13— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-३० के अंतर्गत लेखाधीष्टक २८१०-वैकल्पिक ऊर्जा-आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे ढाला जायेगा।

संलग्न:-यथोक्त।

भवदीय,

(सौरभ जैन)

अपर सचिव।

१२३७

संख्या:-१२३७/।।/2008-03(1)/।।/०९, तददिनांक

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

- १— महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- २— समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- ३— निदेशक, उरेडा, देहरादून।
- ४— सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- ५— नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-२
- ६— प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
- ७— विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,

२०/८
(एम०एम०स०मवाल)
अनु सचिव।

(५८४)